Daily Current Affairs

Date : 15 June, 2026

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	विश्व का पहला RTI लिविंग म्यूज़ियम : नरबद खेड़ा (ब्यावर)
2.	12 राष्ट्रीय कार्यक्रमों/योजनाओं में राजस्थान देश भर में अव्वल
3.	राजस्थान (नमक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन) संशोधन नियम, 2026
4.	राजस्थान का पहला 'डिफेंस एंड एयरोस्पेस पार्क' : उदयपुर खुर्द (किशनगढ़)
5.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (WZCC) की शासी परिषद् की बैठक
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. युवा आपदा मित्र योजना 2. खुश्बी चौधरी : 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में नाम दर्ज 3. ओबेसिटी समिट इंडिया – 2026 4. कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान 5. 'भारत भाग्य विधाता' राजस्थान में टैक्स फ्री
7.	धीरज सेठ
8.	जसपाल राणा
9.	भारत का रोजगार परिदृश्य
10.	ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक
11.	'ऑयलसीड्स किसान मित्र'
12.	विश्व वायु दिवस, 2026
13.	कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन: डॉ. पी.एल. गौतम
14.	प्रोजेक्ट कुशा
15.	भारत का पहला स्वदेशी वार्या वीडियो AI मॉडल

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान परिदृश्य

विश्व का पहला RTI लिविंग म्यूज़ियम : नरबद खेड़ा (ब्यावर)

चर्चा में क्यों?

- नरबद खेड़ा (ब्यावर) में विश्व का पहला 'RTI (सूचना का अधिकार) लिविंग म्यूज़ियम' स्थापित किया जा रहा है।

मुख्य बिन्दु:

- **निर्माण :** इस म्यूज़ियम का निर्माण और संचालन 'स्कूल फॉर डेमोक्रेसी' और 'मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)' द्वारा किया जा रहा है।

- उल्लेखनीय है कि 'सूचना के अधिकार' कानून को लागू करने के लिए ब्यावर में ही 6 अप्रैल, 1996 को देश का पहला विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें 'मज़दूर किसान शक्ति संगठन' ने सूचना में पारदर्शिता लाने के लिए 40 दिनों का धरना दिया था।
- नवनिर्मित RTI म्यूज़ियम को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ RTI आंदोलन के इतिहास को भी दर्ज किया जा सके।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005:

- **संसद द्वारा पारित :** 15 जून, 2005 को।
- **लागू :** 12 अक्टूबर, 2005 को इसकी सभी धाराएँ पूरे देश में पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू।
- **मुख्य उद्देश्य :** नागरिकों को सशक्त बनाना और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देना। यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए कार्य करने योग्य बनाता है।
- यह अधिनियम केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों सहित सरकार के सभी स्तरों पर प्रवर्तनीय है।
- RTI अधिनियम, 2005 की धारा 8(2) (लोक हित का सिद्धांत) और धारा 22 (अधिनियम की सर्वोच्चता) इसके सबसे महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली प्रावधान हैं, जो पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करते हैं।
- **नोट :** महाराष्ट्र के पुणे निवासी शाहिद रज़ा बर्नी द्वारा दायर RTI इस कानून के तहत दायर की गई पहली RTI थी।
- **सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 :** मूल RTI अधिनियम, 2005 के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद ग्रहण करते थे तथा उनका वेतन एवं सेवा की शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होती थीं, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, अब इनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान राज्य सूचना आयोग:

- **गठन :** सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 की धारा-15 के तहत 18 अप्रैल, 2006 को।
- **अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल :** पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
- **राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त -** मोहनलाल लाठर।
- **सदस्य :** सुरेशचंद्र गुप्ता, महेंद्र पारख, टीकाराम शर्मा, सुनील शर्मा।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

12 राष्ट्रीय कार्यक्रमों/योजनाओं में राजस्थान देश भर में अव्वल

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान ने देश में बेहतरीन शासन और नीति क्रियान्वयन का प्रदर्शन करते हुए कुल 12 प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। (आँकड़े: राजस्थान सरकार द्वारा समाचार पत्रों में दिए गए इम्पैक्ट फीचर के आधार पर जून, 2026 तक।)

मुख्य बिन्दु:

क्रम	कार्यक्रम / योजना का नाम	विवरण
1.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	खरीफ सीजन 2025 में 18 करोड़ पॉलिसियाँ तथा रबी सीजन 2025-26 में 1.71 करोड़ पॉलिसियाँ।
2.	पीएम-कुसुम योजना (कम्पोनेंट-A)	अक्षय एवं सौर ऊर्जा स्थापना में।
3.	पीएम-कुसुम योजना (कम्पोनेंट-C):	सौरकृत (Solar-powered) फीडरों की संख्या के आधार पर।
4.	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस - 2025	62,915 स्थलों पर 85 लाख प्रतिभाओं द्वारा भाग लिया गया।
5.	अंगदान एवं प्रत्यारोपण	वर्ष 2025 में राष्ट्रीय पुरस्कार व प्रथम स्थान।
6.	SBM (G) – 'स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025'	लक्षित इकाइयों के रूपांतरण में प्रथम।
7.	फिट इंडिया फ्रीडम रन – 2024	देश के 10,443 कार्यक्रमों में से 6,202 केवल राजस्थान में।
8.	विकसित भारत संकल्प यात्रा	11,209 कैंप, 5.94 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन।
9.	जनजातीय कल्याण एवं सशक्तीकरण	धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट।
10.	तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम	उत्कृष्ट कार्य हेतु WHO द्वारा विशेष तम्बाकू निषेध अवार्ड - 2026
11.	खनिज ब्लॉक	नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन।
12.	पोषण पखवाड़ा - 2026	गतिविधियों में प्रथम स्थान।

राजस्थान (नमक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन) संशोधन नियम, 2026

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान (नमक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन) संशोधन नियम, 2026 को राज्य सरकार द्वारा नमक उद्योग को बढ़ावा देने और नमक उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए लागू किए गए।

मुख्य बिन्दु:

- इसके तहत पूर्व में चल रही आवंटन प्रक्रियाओं और लीज नियमों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया लॉटरी आधारित थी।
- संशोधन नियमों के अनुसार, जिन जिलों में नमक उत्पादन के लिए लवणीय भूमि उपलब्ध है, उनमें सर्वे सीमांकन और भूखंडों के मापन के बाद ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।
- पूर्व के नियमों में लीज समाप्त होने के चार साल बाद तक नवीनीकरण करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं होने से राज्य की लगभग 300 नमक उत्पादक इकाइयाँ लीज नवीनीकरण से वंचित थी। राज्य सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को 6 महीने की एकमुश्त छूट प्रदान कर नमक उत्पादकों को राहत दी गई है।
- **राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें :** माईकाशिष्ट चट्टानों के कारण राज्य के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है।

झील का नाम	संबंधित जिला
सांभर झील	जयपुर, नागौर और अजमेर।
रेवासा झील	सीकर
पचपदरा झील	बालोतरा
डीडवाना झील	डीडवाना-कुचामन
काछौर झील	सीकर
कुचामन झील	डीडवाना-कुचामन
लूणकरणसर झील	बीकानेर
नावां झील	डीडवाना-कुचामन
फलौदी झील	फलौदी
कावोद झील	जैसलमेर
डेगाना झील	नागौर

- **नोट :** राजस्थान का 80-90 प्रतिशत नमक उत्पादन केवल सांभर झील से होता है। सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी एवं देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान का पहला 'डिफेंस एंड एयरोस्पेस पार्क' : उदयपुर खुर्द (किशनगढ़)

चर्चा में क्यों?

- किशनगढ़ (अजमेर) के उदयपुर खुर्द में राजस्थान का पहला 'डिफेंस एंड एयरोस्पेस पार्क' विकसित किया जा रहा है।

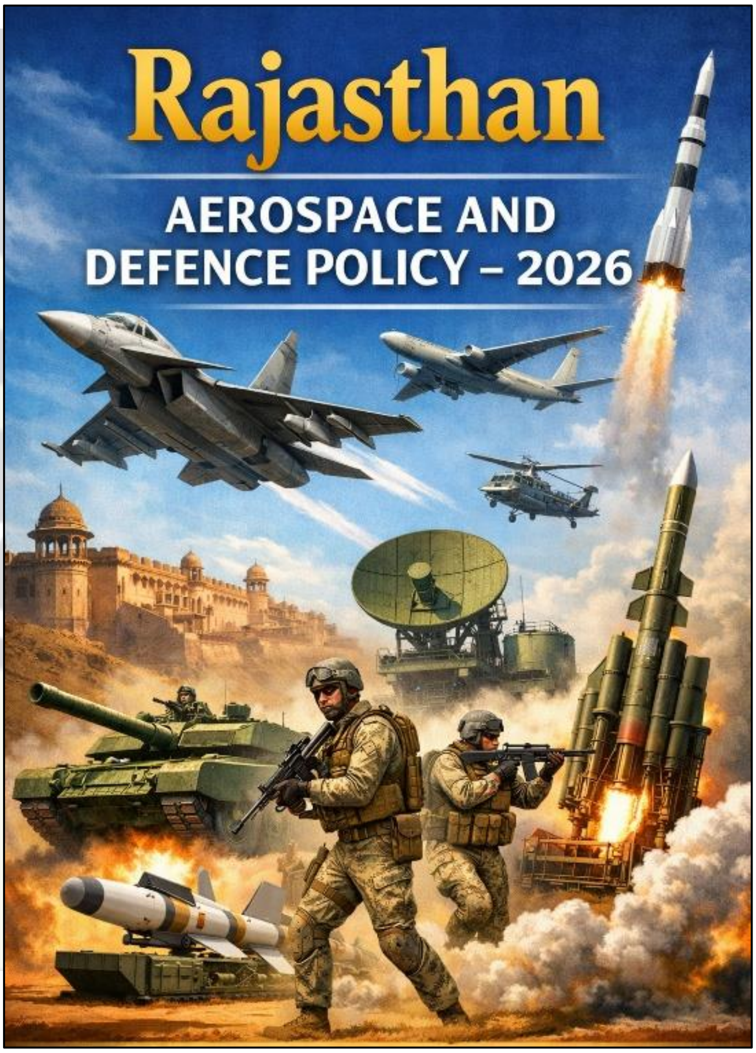

मुख्य बिन्दु:

- 59 हेक्टेयर में विस्तृत इस हब में स्नाइपर राइफल्स, हथियार, ड्रोन और विमान-पुर्जों के निर्माण की अत्याधुनिक इकाइयाँ और टेस्टिंग रेंज स्थापित होगी।

राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेंस पॉलिसी – 2026:

- राजस्थान में रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने तथा राज्य को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के उद्देश्य से 'राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेंस पॉलिसी – 2026' लागू की गई है।
- **अनुमोदन :** राजस्थान मंत्रिमण्डल द्वारा 21 जनवरी, 2026 को।
- **विमोचन :** मुख्यमंत्री द्वारा 18 मार्च, 2026 को जयपुर में आयोजित 'उद्यमी संवाद समारोह' के दौरान।

प्रावधान:

- इस पॉलिसी के तहत MSMEs, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- नीति के अंतर्गत एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उपकरण एवं घटक निर्माता, सप्लायर एवं प्रिसीजन इंजीनियरिंग यूनिट
- MRO (मेंटेनेन्स, रिपेयर एवं ओवरहॉलिंग) इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- यह नीति प्रदेश में रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण :** राजस्थान सरकार द्वारा जारी इस नीति में निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण किया गया है।

विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) :

- ₹50–300 करोड़ – लार्ज।
- ₹300–1000 करोड़ – मेगा।
- ₹1000 करोड़ से अधिक - अल्ट्रा मेगा।

सेवा क्षेत्र (Service Sector) :-

- ₹25–100 करोड़ – लार्ज।
- ₹100–250 करोड़ – मेगा।
- ₹250 करोड़ से अधिक - अल्ट्रा मेगा।

प्रमुख प्रोत्साहन (Incentives) : -

- **एसेट क्रिएशन इंसेंटिव :** नीति के तहत एयरो एण्ड डिफेंस पार्को (A&DP) में लगने वाले पात्र एयरोस्पेस एवं डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और सेवा उद्यमों को एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य कर के 75 प्रतिशत पुनर्भरण का निवेश अनुदान दिया जाएगा।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- विनिर्माण उद्यमों के लिए 20 से 28 प्रतिशत और सर्विस सेक्टर के लिए 14 से 20 प्रतिशत तक 10 वर्षों में वितरित पूँजीगत अनुदान अथवा 10 वर्षों तक वार्षिक किस्तों में देय 1.2 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक टर्नओवर लिंक्ड इन्सेन्टिव में से किसी एक विकल्प का चयन करने की सुविधा दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त इन प्रोत्साहनों पर टॉप-अप के रूप में 10 से 15 प्रतिशत एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, पहली तीन मेगा अथवा अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत सनराइज बूस्टर, 10 प्रतिशत एंकर बूस्टर, 20 प्रतिशत थ्रस्ट बूस्टर जैसे लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
- रीको से भूमि लेने वाले मेगा, अल्ट्रा मेगा विनिर्माण उद्यमों को 10 वर्षों तक फ्लेक्जिबल लैण्ड पेमेंट और 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत ऑफिस स्पेस हेतु लीज रेन्टल सब्सिडी का लाभ भी देय होगा।
- पॉलिसी में विशेष इन्सेंटिव्स का भी प्रावधान किया गया है, जिनमें बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट, फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल, ऑफिस-स्पेस लीज रेंटल सब्सिडी तथा कैप्टिव पावर प्लांट में किए गए निवेश का 51 प्रतिशत पात्र स्थायी पूँजीगत निवेश में शामिल करना है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (WZCC) की शासी परिषद् की बैठक

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, गोवा में 'पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र' की शासी परिषद् की बैठक आयोजित की गई।

मुख्य बिन्दु:

- **बैठक की अध्यक्षता :** राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा।
- **उद्देश्य :** लुप्त होती दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रयास करना।
- ज्ञातव्य है कि शासी परिषद् में भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद से कम रैंक के नामित व्यक्ति, सहभागी राज्य सरकारों द्वारा नामित व्यक्ति और विभिन्न कला विधाओं के प्रख्यात व्यक्तित्व शामिल होते हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर):

- **स्थापना :** 1985 से 1987 के मध्य।
- **अध्यक्ष :** राजस्थान के राज्यपाल।
- **मुख्यालय :** बागोर की हवेली, उदयपुर।
- **उद्देश्य :** प्रदर्शन कला, दृश्य कला, लोक कला, पारंपरिक कला और आदिवासी कला के माध्यम से पश्चिमी भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना।
- **शामिल राज्य और UTs :** राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव।
- पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 'शिल्पग्राम' स्थापित करने वाला भारत का पहला केंद्र था।
- इस केंद्र द्वारा प्रति वर्ष दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में उदयपुर के शिल्पग्राम में 'शिल्पग्राम उत्सव' का आयोजन किया जाता है।
- **नोट :** 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा 114 कोर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर 5961 कलाकारों को लाभान्वित किया गया।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**युवा आपदा मित्र योजना** ■ युवा आपदा मित्र योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राजस्थान पुलिस/SDRF द्वारा संचालित एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आपदा प्रबंधन और राहत-बचाव कार्यों में प्रशिक्षित करना है। ■ इसके तहत राज्य के 13 आपदा-संवेदनशील जिलों में 12,650 स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय विशेष आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ■ प्रशिक्षण शिविरों में एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और स्काउट-गाइड से जुड़े युवाओं को खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, रोप रेस्क्यू और आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ■ आयोजन स्थल : जयपुर स्थित एनसीसी कॉम्प्लेक्स।
2.	**खुश्वी चौधरी : 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में नाम दर्ज** ■ बाड़मेर की 5 वर्षीय स्केटर खुश्वी चौधरी ने हाल ही में रोलर स्केटिंग में 19 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया।
3.	**ओबेसिटी समिट इंडिया – 2026** ■ आयोजन : 13 और 14 जून, 2026 को जयपुर में। ■ आयोजक : एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया (राजस्थान चैप्टर) द्वारा। ■ नोट : ओबेसिटी के खतरे को रोकने और मोटापे से जुड़ी बीमारियों; जैसे - उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फैटी लीवर, घुटने का दर्द, मधुमेह और कैंसर को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग, राजस्थान द्वारा 'मिशन ओबी लॉस' की शुरुआत की गई है।

4.	**कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान** ■ **आयोजन :** चंडीगढ़ में 10 से 13 जून तक। ■ **राजस्थान का प्रदर्शन :** एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक।
5.	**'भारत भाग्य विधाता' राजस्थान में टैक्स फ्री** ■ अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को राजस्थान सरकार ने आधिकारिक तौर पर टैक्स फ्री (कर मुक्त) घोषित किया। ■ यह फिल्म 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमले की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें आतंकी हमले के दौरान मुंबई के कामा अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ द्वारा लगभग 400 मरीजों की जान बचाने के असाधारण साहस और राष्ट्रभक्ति को दर्शाया गया है।

UTKARSH CIVIL SERVICES

राष्ट्रीय परिदृश्य

धीरज सेठ

[स्रोत: PIB]

मुख्य बिन्दु:

- सरकार ने वर्तमान सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को 30 जून, 2026 से अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। जो मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे।
- लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर, 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था।

जसपाल राणा

[स्रोत: AIR]

मुख्य बिन्दु:

- भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का नई दिल्ली में निधन हो गया है।
- राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने में मदद की।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

आर्थिक घटनाक्रम

भारत का रोजगार परिदृश्य

[स्रोत: Indian express]

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में हुई सार्वजनिक बहसों और युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने भारत में रोजगार के मुद्दे पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है।

मुख्य बिन्दु:

रोजगार संकेतक

- **बेरोजगारी दर (यूईआर):** बेरोजगारी दर श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत को मापती है।
- इसकी गणना बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को कुल श्रम बल से विभाजित करके की जाती है जो सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं।
- **श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर):** LFPR से तात्पर्य कामकाजी उम्र की आबादी के उस अनुपात से है जो या तो कार्यरत है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रही है।
- **रोजगार दर (ईआर):** रोजगार दर कामकाजी उम्र की आबादी के उस अनुपात को मापती है जो कार्यरत है।

भारत में रोजगार के प्रमुख रुझान (2016-17 से 2025-26)

- **समग्र रोजगार दर में गिरावट:** भारत की रोजगार दर 2016-17 में लगभग 42.7% से घटकर 2025-26 में 38.7% हो गई है।
- हालांकि नियोजित व्यक्तियों की संख्या लगभग 406 मिलियन से बढ़कर 438 मिलियन हो गई, लेकिन रोजगार में वृद्धि कामकाजी उम्र की आबादी के विस्तार के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही।

- **लिंग के आधार पर रुझान:** पुरुषों की रोजगार दर लगभग 70.5% से घटकर 64.8% हो गई।
- महिला रोजगार दर लगभग 11.8% से घटकर 9.4% हो गई।
- **आयु-वार रुझान:** अधिकांश आयु समूहों में रोजगार दर में गिरावट आई है, केवल 25-29 वर्ष और 55-59 वर्ष की श्रेणियों में मामूली सुधार दर्ज किया गया है।
- **प्रभावित शैक्षिक समूह:** सभी शैक्षिक स्तरों पर रोजगार दर में गिरावट आई, हालाँकि कम शैक्षिक योग्यता वाले लोगों में यह गिरावट अधिक तीव्र थी और स्नातकों में अपेक्षाकृत कम थी।

रोजगार संबंधी चुनौतियों के प्रमुख कारण

- **रोजगारहीन विकास:** आर्थिक विकास पूंजी-प्रधान क्षेत्रों में केंद्रित रहा है, जो सीमित रोजगार अवसर पैदा करते हैं। श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्र बढ़ती कार्यबल को समायोजित करने के लिए पर्याप्त रूप से विस्तारित नहीं हुआ है।
- **संरचनात्मक परिवर्तन की चुनौतियाँ:** श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कम उत्पादकता वाली कृषि पर निर्भर है और कृषि से विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं की ओर संक्रमण अपेक्षा से धीमा रहा है।
- **कौशल का बेमेल होना:** शैक्षिक परिणाम अक्सर उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते हैं।
- **धीमी गति से वैश्वीकरण:** बढ़ते संरक्षणवाद, व्यापार प्रतिबंधों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने निर्यात आधारित रोजगार के अवसरों को कम कर दिया है।
- **तकनीकी व्यवधान:** स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता श्रम बाजारों को बदल रहे हैं। नियमित और दोहराव वाले काम तेजी से तकनीकी प्रतिस्थापन के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं।
- **कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी:** सामाजिक मानदंड, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, अपर्याप्त बाल देखभाल सुविधाएँ और वेतन असमानताएं कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती रहती हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

जीडीपी वृद्धि से अधिक रोजगार क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- जीडीपी वृद्धि आर्थिक उत्पादन के विस्तार को दर्शाती है, लेकिन इसका सीधा संबंध रोजगार सृजन से नहीं है।
- सतत रोजगार सृजन से आय में सुधार होता है, गरीबी कम होती है, सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है और घरेलू माँग मजबूत होती है।
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने के लिए रोजगार-प्रधान विकास आवश्यक है।

रोजगार सृजन के लिए सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना:** एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नौकरी चाहने वालों के लिए कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन और सरकारी और निजी दोनों प्रकार की रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएँ प्रदान करता है।
- **ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान:** स्वरोजगार के लिए उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:** कौशल विकास और स्वरोजगार सहायता के माध्यम से शहरी गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाती है।
- **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को आजीविका चलाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है।
- **पीएम विश्वकर्मा योजना:** यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कौशल विकास, ऋण सहायता और बाजार संपर्क प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:** उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:** रोजगार क्षमता और कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक

[स्रोत: PIB]

चर्चा में क्यों?

- भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक 12 और 13 जून, 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

मुख्य बिन्दु:

- **4 प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार-विमर्श:**

1. प्राथमिकता 1– खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका
2. प्राथमिकता 2 – कृषि व्यापार और सहयोग
3. प्राथमिकता 3 – नवीकरणीय खेती, जलवायु के अनुकूल और संवहनीय कृषि
4. प्राथमिकता 4 – नवोन्मेष के उद्देश्य से सहयोग का सुदृढ़ीकरण तथा कृषि और खाद्य प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने के वास्ते निवेश

परिणाम: संयुक्त घोषणापत्र ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन:

1. **कृषि पारिस्थितिकी एवं पुनर्योजी कृषि हेतु उत्कृष्टता केंद्रों का ब्रिक्स नेटवर्क:** ICAR-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, भारत द्वारा प्रारंभिक समन्वय के साथ कृषि पारिस्थितिकी (एग्रोइकोलॉजी) और पुनर्योजी कृषि (रीजनरेटिव एग्रीकल्चर) पर उत्कृष्टता केंद्रों का ब्रिक्स नेटवर्क स्थापित करने का समझौता है।
2. **'डिजिटल कृषि पर एक नेटवर्क':** सदस्य देश 'डिजिटल कृषि पर एक नेटवर्क' स्थापित करने पर भी सहमत हुए। यह प्लेटफॉर्म कृत्रिम मेधा, भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डेटा-संचालित कृषि समाधानों में सहयोग को बढ़ावा देगा।
3. **'बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों का वैश्विक मंच':** इसमें 'बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों का वैश्विक मंच' की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान, बीज विरासत और किसानों के योगदान को स्वीकार करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है।
4. **'ब्रिक्स एग्रिन':** ब्रिक्स सदस्य देश बीज, कृषि इनपुट्स और आनुवंशिक संसाधनों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 'ब्रिक्स एग्रिन' (एग्रो-इनपुट्स, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क) फ्रेमवर्क स्थापित करने पर भी सहमत हुए।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

'ऑयलसीड्स किसान मित्र'

[स्रोत: PIB]

चर्चा में क्यों?

- हैदराबाद स्थित ICAR-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा 'ऑयलसीड्स किसान मित्र' एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर रही है, जो तिलहन की खेती के बारे में विश्वसनीय, शोध-आधारित ज्ञान को सीधे किसानों के मोबाइल फोन पर, कभी भी और उनकी अपनी भाषा में पहुँचा रही है।

मुख्य बिन्दु:

- **शुभारंभ:** इस सेवा का शुभारंभ 6 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय तिलहन सम्मेलन के दौरान DARE के सचिव और ICAR के महानिदेशक द्वारा किया गया।
- **विकास:** ICAR-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा।
- **सहयोग:** यह ज्ञान आधार राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर, भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान, जूनागढ़, भारतीय रेपसीड और सरसों अनुसंधान संस्थान, भरतपुर और पीसी-यूनिट (तिल और नाइजर) के सहयोग से बनाया गया है, जो भारत के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में सभी प्रमुख तिलहन फसलों को व्यापक रूप से कवर करता है।

प्लेटफ़ॉर्म की प्रमुख विशेषताएँ:

1. **तिलहन फसलों के लिए व्यापक कवरेज:** यह मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और नाइजर सहित सभी प्रमुख घरेलू तिलहन समूहों के लिए सटीक, स्थान-विशिष्ट सलाह प्रदान करता है।
2. **पूर्ण बहुभाषी एकीकरण:** इसमें एक ऐसी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण वास्तुकला है जो सभी आधिकारिक भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं (हिंदी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु और मलयालम सहित) को समझती है और उनमें तुरंत प्रतिक्रिया देती है ।
3. **फसल चक्र के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन**

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

विश्व वायु दिवस, 2026

[स्रोत: PIB]

चर्चा में क्यों?

- विश्व वायु दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

मुख्य बिन्दु:

- भारत ने 15 जून, 2026 को गोवा में "विंड एनर्जी: एम्बिशन टू एक्सेलरेशन" थीम के तहत् विश्व वायु दिवस, 2026 सम्मेलन की मेजबानी की।

- **लक्ष्य:** यह वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट और वर्ष 2035 तक 155 गीगावाट के लक्ष्य के साथ, भारत के वर्ष 2070 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए पवन ऊर्जा महत्त्वपूर्ण है।

भारत का पवन ऊर्जा परिदृश्य:

- भारत में अनुमानित सकल पवन ऊर्जा क्षमता 120 मीटर पर 695.5 GW और ज़मीन से 150 मीटर ऊपर 1,163.9 GW है।
- 150 मीटर पर अनुमानित ऊर्जा क्षमता का ज़्यादातर हिस्सा आठ हाई-रिसोर्स राज्यों में है: राजस्थान: 284.2 GW; गुजरात: 180.8 GW; महाराष्ट्र: 173.9 GW; कर्नाटक: 169.3 GW; आंध्र प्रदेश: 123.3 GW; तमिलनाडु: 95.1 GW; मध्य प्रदेश: 55.4 GW, तेलंगाना: 54.7 GW।
- भारत का बड़ा पवन संसाधन बेस वर्ष 2030 तक 100 GW और वर्ष 2036 तक 156 GW विंड कैपेसिटी पाने के लिए एक मज़बूत आधार देता है।

पवन क्षमता और उत्पादन वृद्धि:

- स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है।
- स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता मार्च, 2014 में 21.04 GW से बढ़कर मार्च, 2026 में 56.09 GW हो गई, जो 2.66 गुना बढ़ोतरी है तथा 28 GW पर काम चल रहा है।
- भारत ने 2025-261 में 6.05 GW की अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा सालाना स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी दर्ज की, जो 2024-25 में 4.15 GW के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई।
- विंड टर्बाइन उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 में 10 GW से बढ़कर मार्च, 2026 तक लगभग 24 GW हो गई है।
- इस क्षेत्र ने सभी ज़रूरी घटकों में 70-80% स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

सरकार की प्रमुख पहल:

- **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF):** 1,000 MW के ऑफशोर पवन परियोजनाओं के लिए ₹6,853 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) को मंजूरी दी गई, जिसमें गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 500-500 MW शामिल हैं।
- **ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स:** इंडस्ट्रीज़ द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की सीधी खरीद को आसान बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स लागू किए गए।
- **पवन ऊर्जा में वैश्विक भागीदारी:** भारत इस क्षेत्र के विकास में तेज़ी लाने के लिए यूके, डेनमार्क और बेल्जियम के साथ पवन ऊर्जा सहयोग को मज़बूत कर रहा है।
- **भारत -यूनाइटेड किंगडम:** भारत-यूनाइटेड किंगडम ऑफशोर विंड टास्कफोर्स को फरवरी, 2026 में विजन 2035 और चौथे इंडिया-यूके एनर्जी डायलॉग के तहत शुरू किया गया था।
- **भारत-बेल्जियम:** वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (WEF) 2026 में, भारत और बेल्जियम ने ऑफशोर विंड, अनुसंधान और विकास, और ग्रीन टैक्सोनॉमी में सहयोग की पुष्टि की।
- **भारत-डेनमार्क:** भारत ने वर्ष 2019 में ऑफशोर पवन क्षमता निर्माण के लिए डेनमार्क के एनर्जी, यूटिलिटीज और क्लाइमेट मंत्रालय के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।

कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन: डॉ. पी.एल. गौतम

[स्रोत: PIB]

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने कृषि जैव विविधता के संरक्षण, सतत् उपयोग और पहुँच एवं लाभ-साझाकरण तथा संबंधित मामलों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 13(1) के अंतर्गत कृषि जैव विविधता पर विशेषज्ञ समिति का एक वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है।

मुख्य बिन्दु:

- **पृष्ठभूमि:** कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति वर्ष 2005 से एनबीए की एक महत्त्वपूर्ण सलाहकार संस्था रही है और कृषि आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता रहा है।
- **समिति के नए अध्यक्ष:** कृषि विज्ञान में पद्म श्री से सम्मानित डॉ. पी.एल. गौतम।
- **सदस्य:** पुनर्गठित समिति में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पादप, पशु एवं मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन, NALSAR विधि विश्वविद्यालय और अन्य प्रमुख अनुसंधान एवं शैक्षणिक संगठनों सहित प्रमुख संस्थानों के प्रख्यात विशेषज्ञ और वरिष्ठ प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।
- **महत्त्व:** यह समिति भारत के अद्यतन NBSAP लक्ष्य 4 और 13 की प्राप्ति में सहयोग करेगी और कृषि आनुवंशिक संसाधनों, देशी फसल किस्मों और पशुधन विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से SDG-2 (शून्य भूख), SDG-13 (जलवायु कार्रवाई) और SDG-15 (भूमि पर जीवन) की प्राप्ति में योगदान देगी।

विज्ञान प्रौद्योगिकी

प्रोजेक्ट कुशा

[स्रोत: THE HINDU]

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी परियोजना कुशा वायु रक्षा प्रणाली को भारत की सुरक्षा संरचना के लिए एक संभावित गेम चेंजर बताया है।

मुख्य बिन्दु:

प्रोजेक्ट कुशा

- प्रोजेक्ट कुशा एक लंबी दूरी की स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे DRDO द्वारा विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों के खिलाफ स्तरीय हवाई रक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- यह प्रणाली रूस के एस-400 ट्रायम्फ जैसे उन्नत प्लेटफार्मों को टक्कर देने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसमें तीन इंटरसेप्टर वेरिएंट होंगे:
    - लगभग 150 किमी की मारक क्षमता वाला M1 इंटरसेप्टर
    - लगभग 250 किमी की मारक क्षमता वाला M2 इंटरसेप्टर।
    - M3 इंटरसेप्टर की मारक क्षमता 350-400 किमी है।
- इस प्रणाली का उद्देश्य लड़ाकू विमानों, जिनमें स्टील्थ प्लेटफॉर्म, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, सटीक निर्देशित गोला-बारूद और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल खतरे शामिल हैं, का मुकाबला करना है।
- यह परियोजना व्यापक "मिशन सुदर्शन चक्र" से भी जुड़ी हुई है, जो 2035 तक भारत के लिए बहुस्तरीय वायु और मिसाइल रक्षा कवच के निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है ।
- इसका परिचालन कार्य 2028 और 2030 के बीच शुरू होने की उम्मीद है ।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

भारत का पहला स्वदेशी वार्या वीडियो AI मॉडल

[स्रोत: PIB]

चर्चा में क्यों?

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले स्वदेशी, संक्षिप्त वीडियो कहानी- उत्पादक एआई मॉडल "वार्या" का अनावरण किया है।

मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** वार्या एक अभूतपूर्व, स्वदेशी फाउंडेशन एआई वीडियो मॉडल है जिसे उन्नत मशीन लर्निंग डिस्टिलेशन का उपयोग करके इंजीनियर किया गया है ।
- यह एक जनरेटिव टेक्स्ट-टू-वीडियो और इमेज-टू-वीडियो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिसे सरल लिखित विचारों, संकेतों या अपलोड की गई छवियों को उच्च-गुणवत्ता वाली, गतिशील डिजिटल कहानियों में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **उद्देश्य:** इस मॉडल का उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों, त्योहारों, समुदायों, खान-पान, पहनावे, सार्वजनिक स्थानों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दृश्य प्रस्तुतियाँ तैयार करना और उन्हें समझना है।
- **विकास:** AI-आधारित परिवर्तन कंपनी 'अवतार' द्वारा।

प्रमुख विशेषताएँ:

1. **लागत-दक्षता:** अवतार के आंतरिक अनुमान-लागत बेंचमार्क के अनुसार, वार्या ₹0.48 प्रति सेकंड की लागत से वीडियो बना सकता है, जो इसे कई प्रमुख वैश्विक वीडियो मॉडलों की तुलना में 10 गुना अधिक लागत-कुशल बनाता है।
2. **डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन की शक्ति:** वीडियो निर्माण को 50 चरणों से घटाकर 4 चरणों तक सीमित कर देती है, जबकि आउटपुट की गुणवत्ता लगभग समान बनी रहती है।
3. **कार्यप्रवाह:** उत्पाद का अनुभव एक सरल वादे पर आधारित है: विचार → वीडियो → कहानी। उपयोगकर्ता अपना विचार लिख सकते हैं, छवि अपलोड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **अवतार:** अवतार एक एआई-आधारित परिवर्तनकारी कंपनी है जो डोमेन-विशिष्ट एआई उत्पाद बनाती है। ये उत्पाद उद्यमों को दक्षता बढ़ाने, नए परिचालन मॉडल विकसित करने और सुरक्षित आईपी-आधारित क्षमताएँ बनाने में मदद करते हैं।
- **डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन:** डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन मशीन लर्निंग की एक मॉडल कम्प्रेशन तकनीक है, जिसमें एक कॉम्पैक्ट "स्टूडेंट" मॉडल एक बड़े, धीमे "टीचर" मॉडल के आउटपुट को दोहराता है, जिससे अनावश्यक गणनाओं को खत्म करते हुए क्षमताओं का स्थानांतरण होता है। वार्या भारत में पहली बार वीडियो के लिए इस अभूतपूर्व तकनीक का उपयोग कर रही है।